(c) whether it is a fact that Banks are co-operating in achieving the targets in the State; and

(d) if so, the reasons therefor and the remedial measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANKER BAKHT): (a) The year-wise targets for beneficiaries under Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) during the last 3 years i.e. 1995-96, 1996-97 and 1997-98 were 22,150 beneficiaries; 22,150 beneficiaries and 21,500 beneficiaries respectively in Bihar.

(b) During this period i.e. 1995-96, 1996-97 & 1997-98, as many as 17,924 beneficiaries; 18,818 beneficiaries and 13,860 beneficiaries for the respective years were sanctioned loan by the Banks in Bihar State.

(c) and (d) The performance of Banks in Bihar as compared to the All India performance has been on the lower side. Monitoring and reviews are done to improve the performance of the scheme from time to time.

Closure of non-SSI industrial units in Gujarat

1248. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly two hundred non-SSI industrial units are lying closed in the State of Gujarat;

(b) if so, the details thereof as on date, industry-wise;

(c) whether Government have prepared any revival plan for these industries; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अमरीकी कंपनियों द्वारा पेटेंट कराया जाना

1249. **श्री रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या **उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका द्वारा बौद्धिक, जैविक संपंदा तथा चिकित्सा के लिए उपयोगी वनस्पतियों सहित अब तक किन-किन वस्तुओं का पेटेंट करने का प्रयास कर रहा है।

(ख) क्या सरकार पहले से पेटेंट की गई वस्तुओं को अमरीकी पेटेंट कानून से मुक्त कराने तथा इस प्रथा को रोकने के लिए कोई ठोस/प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना नही रखी जाती है। तथापि, वनस्पतियों के लिए पेटेंटा मंजूर नही किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त, पेटेंटों की मंजूरी विभिन्न सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के तहत दी जाती है। जब कभी उन कुछेक उत्पादों, जिन्हें पेटेंट –योग्य नही समझा जाता है, पर पेटेंट लेने के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो इस बात को निश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं कि क्या पेटेंट प्रदान करने को चुनौती दी जा सकती है। इस संबंध में पर्याप्त सामग्री एकत्रित किए जाने के बाद उस देश में पेटेंट की पुनः जांच कराए जाने और अन्ततः उसे रद्द करने हेतु एक याचिका दायर करने के लिए कदम उठाएं जाते है।

Enlistment of Sick PSUs with BIFR

1250. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to-state:

(a) the number of sick CPSUs enlisted with BIFR;

(b) the total number of employees in the above units including contract/casual labour;

(c) the number of ancillary units associated with the above CPSUs; and

(d) the Government's action plan to revive these units alongwith the timeframe for the same?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) As on